छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधान सभा
पंचम सत्र

लेफ्टि.जन. के.एम. सेठ

पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम.(से.नि.)

राज्यपाल, छत्तीसगढ़

का

अभिभाषण

दिनांक 21 फरवरी, 2005

माननीय सदस्यगण,

आप सभी को नववर्ष 2005 की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ की दूसरी विधानसभा का एक वर्ष पूरा हुआ है तथा यह नए साल का पहला सत्र है। इस बीच राज्य में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव भी सफलता एवं शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं। लोकतंत्र की इस सर्वोच्च संस्था के माध्यम से मैं आप सभी का, और राज्य की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिनके सहयोग से लोकतंत्र की प्राथमिक इकाइयों में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के माध्यम से नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

2. अपने संकल्पों और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में मेरी सरकार ने जो कदम उठाए थे, उनमें से बहुत से कदम अपने लक्ष्यों तक पहुंच रहे हैं। मैंने विगत सत्र में कहा था कि राज्य में समरसता के साथ विकास का नया सफर शुरु हुआ है। आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार के सकारात्मक प्रयासों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केन्द्रीय शासन के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अन्य स्वतंत्र और प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा किए गए सर्वेक्षणों द्वारा भी मान्यता मिल रही है। सरकार की सही नीतियों और सदाशयता से छत्तीसगढ़ की पहचान, एक उभरते हुए राज्य के रुप में होने लगी है।

3. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार विगत वर्ष छत्तीसगढ़ में हुआ निवेश भारत में हुए निवेश का 10.22 प्रतिशत है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। विगत एक वर्ष में 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक के पूंजी निवेश के एम.ओ.यू. विभिन्न संस्थाओं से किए जा चुके हैं। इन समझौतों को कार्यरुप में ढालने के लिए सहयोगी वातावरण बनाने हेतु मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003–04 में 1057.82 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया, जो विगत वर्ष हुए 425 करोड़ रुपए के निर्यात की तुलना में, 632 करोड़ अर्थात 148.78 प्रतिशत अधिक है। मेरी सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2005–06 की वार्षिक योजना के लिए 4275 करोड़ रुपए की स्वीकृति, भारत के योजना आयोग से प्राप्त करने में सफलता हासिल की है, यह विगत वर्ष की तुलना में 953 करोड़ रुपए अर्थात 28.67 प्रतिशत अधिक है।

4. इन संकेतकों के जरिए मैं यह कहना चाहता हूं कि चौतरफा विकास की जो रणनीति बनाई गई थी, उसके परिणाम दिखने लगे हैं और इस अवसर को गंभीरता से समझने के साथ, इसकी निरंतरता जारी रखने की जरुरत है। मेरी सरकार की राय स्पष्ट है कि राज्य के वित्तीय संसाधनों में लगातार बढ़ोत्तरी जरुरी है। विभिन्न स्त्रोतों से, चाहे वह केन्द्रीय संसाधनों में हमारे राज्य का हिस्सा हो, चाहे राजस्व में बढ़ोत्तरी या निजी पूंजी निवेश का प्रवाह, इन सभी तरह के प्रयासों से ही राज्य में अधोसंरचना विकास और जरुरतमंद तबकों के हित के काम तेजी से करने के संसाधन जुटाए जा सकते हैं।

5. अपनी रणनीति से पैदा हुए विश्वास के कारण ही, मेरी सरकार ने किसानों को सहकारी बैंकों से 9 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने का फैसला किया। देश में किसानों को सबसे कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराने की इस पहल का लाभ, राज्य के 11 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा। समर्थन मूल्य पर किसानों को धान खरीदने के फैसले पर दृढ़ता से अमल करने की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि इस वर्ष 28.50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का नया कीर्तिमान बनाया गया। इस काम में लगभग 1650 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई। मेरी सरकार ने बड़ी लगन और कुशलता से यह कार्य किया।

6. किसानों की माली हालत सुधारने के लिए मेरी सरकार ने पहले लघु और सीमांत किसानों के अल्पकालिन ऋण माफ किए और 6 लाख से अधिक किसानों को 118.36 करोड़ रुपए का लाभ दिया। फिर बकाया सिंचाई कर की 40 प्रतिशत राशि माफ कर, 2.60 लाख किसानों को 8.55 करोड़ रुपए का लाभ दिलाया। फिर सिंचाई पंपों के कनेक्शन देने के लिए विद्युत मण्डल द्वारा अनुदान की राशि भी 30 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दी गई है। गन्ना किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करना तब–तक बेमानी है, जब तक उनकी उपज के दाम नहीं बढ़ाए जाएं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने गन्ने की खरीदी पर बोनस में 10 रुपए की वृद्धि कर, खरीदी दर प्रति क्विंटल 95 रुपए कर दी है। प्रमाणित बीजों के दामों में भी कमी की गई है। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों को आर्थिक सहायता दी गई।

7. राज्य के नदी–नालों एवं जलाशयों के समीप भू–जल अपेक्षाकृत कम गहराई में मिलता है। इन क्षेत्रों में शैलो ट्यूबवेल के माध्यम से सुनिश्चित सिंचाई का रकबा बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। मेरी सरकार ने इस दिशा में अभिनव पहल करते हुए, आगामी तीन वर्षों में 30 हजार शैलो ट्यूबवेल स्थापित करने हेतु किसानों को अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इससे उपलब्ध भू–जल का पर्याप्त दोहन हो सकेगा और तीन वर्षों में एक लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई क्षमता बढ़ सकेगी।

8. मेरी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अभी तक राज्य में करीब एक लाख किसान ही सिंचाई पंपों का उपयोग करते हैं। इसमें क्रांतिकारी बदलाव की जरुरत महसूस करते हुए, यह फैसला किया गया है कि आगामी तीन वर्षों में सिंचाई पंपों को दो गुना कर दिया जाए। इस तरह आगामी तीन वर्षों में एक लाख किसानों को सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दिए जाऐंगे। इस कार्य की शुरुआत शीघ्र की जाएगी।

9. मछली पालन के क्षेत्र में लगे किसानों को प्रोत्साहित करने में भी मेरी सरकार ने अच्छी सफलता हासिल की है। मछली बीज तथा मत्स्य उत्पादन में लगभग डेढ़ गुना वृद्धि कर छत्तीसगढ़, भारत के अव्वल आठ राज्यों में शामिल हो गया है। राज्य में 5 नई मछली बीज हैचरी स्थापित की गई। समन्वित मछली पालन के तहत 68 नई इकाइयां स्थापित की गई हैं। 130 नए तालाब बनाकर मछली कृषकों को दिए गए हैं। मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना बिलासपुर में की गई है।

10. राष्ट्रीय गौवंशीय–भैस वंशीय प्रजनन परियोजना के अंतर्गत दुधारु पशुओं की नस्ल में सुधार हेतु 10 करोड़ रुपए की लागत से कृत्रिम गर्भाधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के माध्यम से 15.50 करोड़ रुपए की लागत से महत्वाकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन रायगढ़, अंबिकापुर, कवर्धा, कोरिया, जशपुर जिलों में शुरु किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का गठन, दुग्धमार्गों का निर्धारण, विपणन की रणनीति संबंधी काम शीघ्र ही पूर्ण कर लिए जाएंगे।

11. मेरी सरकार ने करों के युक्तियुक्तकरण और नियोजित प्रशासनिक उपायों से राजस्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। वाणिज्य कर संग्रहण में 22 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है। वहीं जरुरतमंद तबकों को मदद करने के लिए आवश्यकतानुसार करों में रियायतें भी दी गई हैं। कृषि–वन–फूल–पशुधन आधारित प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण हेतु लगाए जाने वाले नए उद्योगों को स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है। बीमार उद्योगों के लिए प्रतिभूतियों से ऋण की रकम पर मुद्रांक शुल्क एक लाख रुपए अधिकतम तक सीमित किया गया है। किसानों को अल्पकालिक ऋणों के लिए बैंको के साथ करार के लिखतों पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई। स्व–सहायता समूहों को आर्थिक उत्थान के लिए ऋण संबंधी दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क से छूट दी गई।

12. मेरी सरकार ने दूरदर्शितापूर्वक त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के पहले ही, पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर ऐसे प्रावधान कर दिए थे कि ग्रामसभा का सशक्त बनाने, साक्षरता और स्वच्छता को जनअभियान का रुप देने की तैयारी हो जाए। इससे वे लोग ही जनता की अदालत में भाग्य आजमा पाए, जिनकी प्रतिबद्धता गांवों के सार्थक विकास के लिए हो।

13. पंचायतों की कार्य प्रणाली में सुधार तथा कुशलता लाने के लिए मेरी सरकार ने 26 जनवरी से राज्यव्यापी "ई–पंचायत योजना" शुरु की है। इससे प्रदेश की सभी जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों को "वी–सेट" के जरिए, राज्य मुख्यालय से जोड़ दिया गया है। इससे पंचायतों की प्रगति का मूल्यांकन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से हो सकेगा। पंचायतों के माध्यम से संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ बेहतर ढंग से लोगों को मिल सकेगा। पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए धमतरी तथा रायगढ़ में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

14. गांवों से गरीबी का रिश्ता समाप्त करने के प्रयासों के तहत, मेरी सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से गरीबी उन्मूलन परियोजना "नवा अंजोर" शुरु की है। वही "समविकास योजना" के अंतर्गत पिछड़े और न्यून विकास दर वाले 8 जिलों का चयन किया गया है। 10 जिलों में "काम के बदले अनाज योजना" संचालित की जा रही है। इन योजनओं पर काम शुरु हो जाने से जरुरतमंद तबकों को बड़ी राहत मिलने लगी है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के 2 हजार 198 आवासहीन परिवारों के लिए नए आवास बनाये जा रहे हैं।

15. गांवों में जरुरी अधोसंरचना के विकास हेतु मेरी सरकार द्वारा शुरु की गई अभिनव योजनाओं यथा "ग्रामीण सचिवालय", "गृह लक्ष्मी", "निर्मलाघाट", "सद्भावना भवन निर्माण", "गौठान निर्माण", "कांजी हाऊस निर्माण", "मुक्तिधाम", "केशवकुंज", गांव की "गलियों का सीमेन्ट– कांक्रीटीकरण" में अच्छी प्रगति दर्ज की गई है।

16. मुझे खुशी है कि मेरी सरकार, "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" का लाभ उठाने वाले राज्यों में अग्रणी रही है। इस योजना के तहत विगत एक वर्ष में 233.68 करोड़ रुपए की लागत से 1022.25 कि.मी. लंबी, 203 सड़कों तथा 2174 पुल–पुलियों का निर्माण पूरा किया गया है। सीमित संसाधनों और वर्ष में 87 करोड़ रुपए के आबंटन के विरुद्ध 412.58 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त करना भी एक उपलब्धि है।

17. ग्रामीण विकास के लिए–चहुंमुखी प्रयास करने हेतु तीन नई योजनाएं आगामी वित्तीय वर्ष से लागू की जाएंगी। छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों के जन्मस्थल को समग्र रुप से विकसित करने और समस्त कल्याणकारी योजनाओं को कारगर ढंग से लागू करने हेतु "छत्तीसगढ़ गौरव योजना" शुरु की जाएगी। इसके तहत चयनित गांवों को आदर्श गांव के रुप में विकसित किया जाएगा। ग्रामीण अंचल की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विकासखंड स्तर पर हाईस्कूल एवं उच्च शालाओं में पांच एकड़ की भूमि को "इन्द्रप्रस्थ" योजना के तहत सुविधाजनक खेल मैदान के रुप में विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार प्रदेश में पुरातत्व महत्व के स्थलों पर आने वाले पर्यटकों के लिए अधोसंरचना विकसित करने हेतु "हमारा छत्तीसगढ़" योजना शुरु की जाएगी।

18. मेरी सरकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों, धरोहरों, पर्यटन स्थलों पर गौरव करने के साथ ही, इन तक लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए अधोसंरचना का विकास सबसे जरुरी समझती है। इस दिशा में निश्चित रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण अंचल में स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के लिए ऐसे पर्यटन स्थलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे डामरीकृत पहुंच मार्ग, पेयजल, प्रतीक्षालय, शौचालय आदि बनाने की योजना शुरु की जा रही है। प्रत्येक जिले में प्रमुख राजमार्गों पर हाईवे मोटल बनाने की निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित हाईवे मोटलों में रेस्टोरेंट एवं आवासीय व्यवस्था के अतिरिक्त, सूचना केन्द्र का प्रावधान भी किया जाएगा।

19. राज्य में उपलब्ध पुरासंपदा के संरक्षण और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण जिलों में "जिला पुरातत्व संग्रहालय" स्थापित किए जाएंगे। पुरातात्विक स्मारकों को पर्यटन स्थल के रुप में विकसित करने का काम हाथ में लिया गया है। संस्कृति और पारंपरिक कलाओं से समृद्ध छत्तीसगढ़ के गांव–गांव में बसे विभिन्न विधाओं के कलाकारों को सूचीबद्ध करने हेतु "चिन्हारी योजना" शुरु की गई है।

20. राज्य में अच्छी सड़कों का जाल बिछाने के लिए लगभग 6 हजार कि.मी. सड़कों, 182 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। उत्तर–दक्षिण तथा पूर्व–पश्चिम कॉरीडोर विकसित करने की दिशा में 375 कि.मी. सड़कों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विभिन्न योजनाओं के तहत तीव्रगामी सड़कों, पुलों–पुलियों तथा फ्लाई ओव्हरों के निर्माण की गति बढ़ाई जा रही है। सड़कों को बेहतर बनाने हेतु सरकार "एशियन विकास बैंक" का सहयोग भी प्राप्त कर रही है।

21. आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक वर्ग का उत्थान एक ऐसी चुनौती है, जिसके लिए विगत दशकों से सीख लेने और नए सिरे से विचार करने की जरुरत है। इस पृष्ठभूमि में मेरी सरकार ने "बस्तर", "सरगुजा–जशपुर" तथा "अनुसूचित जाति" विकास प्राधिकरणों का गठन किया। इन प्राधिकरणों की बैठकों में, संबंधित वर्गों के जनप्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं और समस्याओं पर विचार करते हुए, तत्काल निर्णय लेने की नई शैली विकसित की गई। इन क्षेत्रों के विकास के वर्षों से लंबित कार्य, मिनटों में मंजूर किए जाते हैं। "बस्तर" तथा "सरगुजा–जशपुर" विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों पर एक वर्ष के भीतर ही 25 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की गई है।

22. "अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण" की पहली बैठक में, 100 गांवों में "बाबा गुरु घासीदरास मंगल भवन" का निर्माण, 100 गांवों में गलियों में खड़ंजा निर्माण या सीमेन्ट–कांक्रीटीकरण, 100 गांवों में हैण्ड पंपों की स्थापना, 100 गांवों में विद्युतीकरण, युवाओं को स्व–उद्यम के लिए आर्थिक सहायता, जिलों में "अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम" के कार्यालय खोलने जैसे अनेक कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्णय लिए गए।

23. मेरी सरकार, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आदिवासी परिवारों को एक–एक "दुधारु गाय" प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से कार्य योजना बनाकर गाय वितरण का कार्य 26 फरवरी से शुरु किया जा रहा है। पहले चरण में 10 हजार गायें उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। जैसे–जैसे गायें उपलब्ध होती जाएंगी, वैसे–वैसे वितरण का कार्य किया जाएगा। इस संबध में मेरी सरकार ने काफी अध्ययन और गंभीरता से कदम उठाया, ताकि इन गायों का लाभ आदिवासी परिवार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उठा सकें। बाकायदा मिल्करुट तय कर, गायों के रखरखाव का प्रशिक्षण देकर ही, दस विकासखंडों का चयन, पहले चरण में गाय वितरण के लिए किया गया है। यह विषय ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा मानवीय पहलुओं से जुड़ा है, इसलिए मेरी कामना है कि इसे सफलतापूर्वक अंजाम देने में सभी का सहयोग प्राप्त हो।

24. राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 65 प्रतिशत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार, साक्षरता में वृद्धि के लिए 400 शिक्षण संस्थाओं तथा आश्रम भवनों का निर्माण किया जा रहा है।

25. वनों की सुरक्षा के साथ वनवासियों का विकास बड़ा ही संवेदनशील मामला है। मेरी सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से बड़ी सकारात्मक राह निकाली है। लगभग 7 हजार वन सुरक्षा तथा ग्राम वन समितियों को आर्थिक रुप से सक्षम बनाने हेतु वनों के विदोहन से प्राप्त राशि में से 17.53 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। राष्ट्रीय वनीकरण योजना के अंतर्गत 27 वन विकास अभिकरणों के माध्यम से लगभग 68 करोड़ रुपए की योजनाएं, वनों के विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही हैं।

26. विभिन्न वन समितियों द्वारा दवा निर्माण हेतु लायसेंस प्राप्त कर विगत वर्ष लाखों रुपए मूल्य की औषधियां बेची गईं। अकाष्ठीय लघु वनोपजों के चिन्हांकन एवं प्रसंस्करण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उच्चगुणवत्ता के औषधीय पौधों के उत्पादन हेतु 27.50 लाख रुपए की तीन वर्षीय योजना शुरु की गई है। वन प्रबंधन को अधिक जनोन्मुखी बनाते हुए लोक संरक्षित क्षेत्रों मे 66 प्रसंस्करण केन्द्रों तथा 39 वन औषधालयों की स्थापना की गई। इससे आदिवासियों को सतत रोजगार और उनके द्वारा संग्रहित लघु वनोपजों का अधिक मूल्य मिलेगा। लघु वनोपजों के सुरक्षित भंडारण हेतु 47 गोदामों का निर्माण किया जा रहा हैं। वर्ष 2003 के तेन्दूपत्ता के प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रुप में 33.16 करोड़ रुपए का वितरण, संग्राहकों को किया जा रहा है।

27. मेरी सरकार ने वनों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ–साथ वनाश्रित लोगों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बिगड़े वनों और बांस वन क्षेत्रों का सुधार कार्य भी किया है। इससे भविष्य में अधिक तथा अच्छी गुणवत्ता के बांस उत्पादित हो सकेंगे, जो कुटीर उद्योगों में रोजगार बढ़ाने के काम आएंगे। राज्य की जैवविविधता और दुर्लभ वनौषधियों का वनवासियों की आजीविका का साधन बनाने के लिए मेरी सरकार ने "राज्य वनौषधि बोर्ड" का गठन किया है। इसके तहत 32 वन मण्डलों में लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना कर, 1,14,500 हेक्टेयर में वनौषधियों का संरक्षण और संवर्धन करवाया गया है। निजी क्षेत्रों की भागीदारी भी औषधीय पौधों के उत्पादन में बढ़ाई गई है।

28. भू–स्वामियों को उनकी भूमि पर खड़े वृक्षों को काट कर बेचने की सुविधा देने हेतु, भू–राजस्व संहिता को सरलीकृत किया गया है। इनका परिवहन सुगम बनाने के लिए सात प्रजातियों का परिवहन अनुज्ञा पत्र से मुक्त किया गया है। अन्य सात प्रजातियों के परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने का अधिकार पंचायतों को दिया गया है।

29. मेरी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। "छत्तीसगढ़ सर्वाजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2004" के तहत सभी जिलों की निजी उचित मूल्य दुकानें निरस्त की जा रही हैं। उनके स्थान पर आदिमजाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (लेम्प्स), ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों, वन सुरक्षा समितियों एवं स्व–सहायता समूहों को राशन दुकानें उपलब्ध कराई जा रही हैं। राशन दुकानों के संचालन में पिछडे तबकों और महिलाओं की

सहभागिता के इंतजाम किए गए हैं। यह देश में अपने प्रकार की अनूठी पहल है। इन प्रयासों से खाद्यान्न के उठाव में तेजी आई है और विगत वर्ष तथा राष्ट्रीय औसत उठाव की तुलना में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है।

30. दूरस्थ अंचलों तथा गरीब परिवारों को आयोडीनयुक्त नमक सहजता से उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई 'छत्तीसगढ़ अमृत नमक' योजना का लाभ 23.45 लाख परिवारों को मिलने लगा है। 25 पैसे किलो की दर से दो किलो नमक मिलने से इन परिवारों को जो स्वाद के साथ सेहत सुधारने की नई सुविधा भी मिली है। किसी समय शोषण का प्रतीक रहा नमक अब मेरी सरकार के प्रयासों से सामाजिक न्याय का प्रतीक बन गया है।

31. 'अन्नपूर्ण दाल–भात योजना' के तहत 146 विकासखंड एवं जिला मुख्यालयों में 5 रूपए में भरपेट दाल–भात मिलने की तृप्ति का आनंद तो जरूरतमंद तबका ले ही रहा है, इससे समाज में ऊंच–नीच की भावना को कम करने में भी मदद मिली है। अब मेरी सरकार द्वारा दाल–भात केन्द्रों की बी.पी.एल. दर पर चावल, 60–60 लीटर क्षमता के दो तथा 35 लीटर का एक प्रेशर कुकर तथा निःशुल्क गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मेरी सरकार के विशेष प्रयासों से विशेष पिछड़ी जनजाति के समस्त परिवारों को 'अंत्योदय अन्न योजना' का लाभ देना शुरू किया गया है। अत्यंत गरीब 1.38 लाख नवीन परिवारों को चिन्हांकित कर उन्हें भी राशन कार्ड दिए गए हैं। 4.62 लाख अत्यंत गरीब परिवारों को अत्यधिक रियायती दर पर, प्रतिमाह 35 किलो चावल 3 रूपए की दर से दिया जा रहा है। 'अन्नपूर्णा योजना' के तहत 65 वर्ष या अधिक के बेसहारा वृद्धों को, प्रतिमाह 10 किलो चावल, निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है।

32. मेरी सरकार, भूमि तथा उससे जुड़ी राजस्व संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रशासनिक तथा प्रौद्योगिकी, दोनों प्रकार के उपाय अपनाकर आम जनता के माथे से चिंता की लकीरें मिटाना चाहती है। विशेष अभियान चलाकर नामांतरण तथा बंटवारे के प्रकरणों का निराकरण छह माह के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। 'भुइंया' कार्यक्रम के तहत किसानों या आम जनता को नक्शा, खसरा एवं बी–वन की कम्प्युटरीकृत प्रतियां उपलब्ध कराने के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राज्य, जिला मुख्यालय, अनुविभाग तथा राजस्व निरीक्षक मुख्यालय स्तरों पर कम्प्यूटर कक्ष तथा उपकरणों की स्थापना की जाएगी। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, उनका पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण कार्य सुचारू रूप से करने के लिए, मेरी सरकार ने समस्त तहसीलों हेतु एक–एक जीप प्रदाय करने का निर्णय लिया है।

33. अबूझमाड़ में विकास की रूपरेखा बनाने के लिए, अंचल के 237 गांवों के हवाई सर्वेक्षण, हवाई फोटोग्राफी से नक्शों एवं भू–अभिलेख तैयार करने के लिए मेरी सरकार ने भारतीय दूर संवेदन संस्थान, हैदराबाद के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए हैं।

34. मेरी सरकार, महिलाओं की शिक्षा और सेहत पर ध्यान देने के साथ, उनके अधिकारों की रक्षा हेतु उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। लगभग 70 हजार ''महिला स्वसहायता समूहों'' को सुनियोजित तरीकों से आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने हेतु बहुआयामी कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। 'छत्तीसगढ़ महिला कोष' द्वारा स्वसहायता समूहों को दी जाने वाली ऋण राशि को 5 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रूपए कर दिया गया है। इस योजना का विस्तार शहरी क्षेत्रों में भी किया जाएगा।

35. बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मेरी सरकार द्वारा महिला स्वसहायता समूहों की तर्ज पर 'नारी संबल समूह' तथा 'किशोरी शक्ति समूहों'' को प्रेरित किया जा रहा है। इनके माध्यम से 114 विकासखंडों में सुपोषण अभियान प्रारम्भ किया गया है। प्रदेश में आगामी तीन वर्षों में 10 हजार आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण की दिशा में, इस वर्ष 600 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन बनाए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु एक राज्य स्तरीय तथा दो क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

36. मेरी सरकार, निःशक्तजनों को समाज का अभिन्न अंग तथा उनका विशेष ध्यान रखने को अपना कर्तव्य मानती है। इस दिशा में संगठित कार्यवाही करते हुए 'दीनदयाल निःशक्तजन पुनर्वास' कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 57 हजार निःशक्तजनों का प्रमाणीकरण कर उन्हें प्रमाण पत्र, परिचय पत्र एवं पास–बुक जारी किए गए। इन दस्तावेजों से सेवा संसाधनों का अभिलेख सुरक्षित रखा जा सकेगा। निःशक्तजनों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने, उन्हें प्रशिक्षण और आवश्यक वित्तीय सहायता देने हेतु 'छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम' की स्थापना की गई है, जिसकी अंश पूंजी 5 करोड़ रूपए है। इसके अलावा तीन नए जिलों राजनांदगांव, बस्तर तथा जशपुर में 'जिला पुनर्वास केन्द्र' प्रारम्भ किए गए हैं। शेष 9 जिलों में आगामी वर्षों में ऐसे केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

37. मेरी सरकार ने विश्वविद्यालयों की गरिमा, गुणवत्ता और नई पीढ़ी में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए तीन नए क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तीन नए विश्वविद्यालय शुरू करने की तैयारी की है। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, पं. सुन्दर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय तथा कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय आगामी सत्र से कार्य करने लगेंगे। पूर्व से कार्यरत विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है।

38. मेरी सरकार ने शासकीय महाविद्यालयों तक आम और ग्रामीण युवाओं की आसान पहुंच को देखते हुए इन्हें नई सुविधाएं देने का अभियान शुरू किया है। 116 शासकीय महाविद्यालयों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। महाविद्यालयों को 'सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस' का दर्जा देने का प्रस्ताव यूजीसी को भेजा गया है। व्यावसायिक और 'ऐड आन' पाठ्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। शासकीय कॉलेजों की गुणवत्ता में सुधार के लिए 'नैक' से मूल्यांकन कराया जाएगा। महाविद्यालय भवनों और छात्रावासों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

39. मेरी सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े 'रायपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय' को 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान' का दर्जा दिलाने में सफलता मिली है। रायपुर और बिलासपुर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 'ई–क्लास रूम' योजना आई.आई.टी. कानपुर के सहयोग से शुरू की गई है। रायपुर और जगदलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को उन्नत करने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं।

40. प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा को मजबूत बनाकर ही शिक्षित राज्य की कल्पना, मेरी सरकार ने की है। इसके लिए प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए गए हैं। विशेष अभियान चलाकर 98.92 प्रतिशत बच्चों को विभिन्न शालाओं में प्रवेश दिलाया गया। 3 हजार 321 भवन, 4 हजार 104 अतिरिक्त कक्ष, 887 संकुल केन्द्र भवनों का निर्माण तथा 778 प्राथमिक शाला से पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन, 423 नवीन प्राथमिक शाला, एक हजार 738 शालाओं में पेयजल की व्यवस्था, 5 हजार 524 शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 27 हजार 931 प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं को 5 हजार रूपए प्रति शाला की दर से मरम्मत अनुदान दिया गया है।

41. प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 22 हजार 249 संविदा शिक्षकों की भर्ती हेतु पद निर्मित किए गए हैं। हाईस्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भवन बनाने के लिए 10 करोड़ रूपए तथा फर्नीचर के लिए एक करोड़ रूपए की लागत से कार्य शुरू किया गया। 58.26 लाख स्कूली और महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं को 10 हजार रूपए तक की दुर्घटना बीमा सुरक्षा दी जा रही है। प्राथमिक स्तर की 25.22 लाख छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा बुक बैंक योजना में अनुसूचितजाति तथा जनजाति के बालक–बालिकाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की गई। आगामी शिक्षा सत्र से 10 वीं तक की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में, खाना पकाने के लिए पूर्व निर्धारित दर बढ़ाकर दोगुनी की जा रही है तथा शासकीय प्राथमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन पकाने के लिए गैस कनेक्शन एवं प्रेशर कुकर देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही किचन शेड का निर्माण भी करने का निर्णय लिया गया है।

42. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2.50 लाख बालिकाओं को 2 करोड़ रूपए का गणवेश दिया गया। शासकीय हाईस्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति की 2,320 बालिकाओं को निःशुल्क सायकल दी जा रही है। इस वर्ष प्रदेश में 49 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, इनके भवनों का शिलान्यास भी 26 जनवरी को कराया जा चुका है। बालिकाओं में शिक्षा के साथ आत्मनिर्भरता के गुण विकसित करने के लिए बालिका छात्रावासों में सिलाई मशीन तथा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

43 मेरी सरकार, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं की क्रांति लाना चाहती है, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और यह कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ हो। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को मॉडल स्कूल के रुप में विकसित करने, हर जिले में एक आधुनिक सुविधायुक्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण भवन

की स्थापना का कार्य शुरु किया गया है। 5 बीटीआई को डाइट में उन्नत करने और 4 नए डाइट की स्थापना का कार्य शुरु किया गया है। इतना ही नहीं प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में कार्यरत लगभग 92 हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्य शुरु किया जा रहा है तथा प्रशिक्षण हेतु "सी–नेट' की स्थापना की गई है। अगले शिक्षा सत्र से योग को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है और इसके लिए व्यायाम शिक्षकों, छात्रावास तथा आश्रम अधीक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

44. मेरी सरकार, शिक्षा की तरह खेल को भी जीवन का एक अनिवार्य अंग मानती है और इसलिए राज्य में स्तरीय खेलकूद सुविधाएं बढ़ाने के लिए सुनियोजित कदम उठा रही है। प्रत्येक जिला मुख्यालय में खेलों की उपयुक्त अधोसंरचना विकसित करने के लिए हर जिला मुख्यालय में प्रारंभिक कार्य शुरु किया गया है। राज्य शासन द्वारा पहली बार खेल "कैलेण्डर स्पोर्टस विजन– 2005" तैयार किया गया है। इसके अनुसार राज्य शासन द्वारा सहायता और सुविधा प्रदान कर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं।

45. खेल प्रतिभाओं को प्रेरित करने के लिए लाखों रुपए के पुरस्कार, अलंकरण और प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। खेल अलंकरण पुरस्कार नियम बनाकर, खेल गतिविधियों को संचालन पारदर्शिता के साथ सुचारु रुप से किया जा रहा है। इस वर्ष खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को 32 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए। छत्तीसगढ़ मैराथन में प्रथम आने वाले महिला/पुरुष को एक–एक लाख रुपए की नगद राशि देने की घोषणा की गई है। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय चैम्पियनशिप एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर नियमानुसार यात्रा व्यय राज्य शासन द्वारा वहन करने की सुविधा शुरु की गई है।

46. जनस्वास्थ्य की देखभाल तथा उपचार सुविधाएं बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने कारगर प्रबंध किए हैं। सुदूर ग्रामीण और पहुंच विहीन क्षेत्रों में 874 नए उप स्वास्थ्य केन्द्र इसी वर्ष से कार्य करने लगेंगे। आदिवासी बहुल, "बस्तर" तथा "सरगुजा–जशपुर" विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में चलित चिकित्सालय की सुविधा शुरु की गई है। छत्तीसगढ़ में विशेष जातियों में पाई जाने वाली आनुवांशिक बीमारी सिकलसेल एनीमिया के निदान हेतु प्रदेश स्तरीय कार्य योजना का क्रियान्वयन शुरु किया गया।

47. डेनिडा परियोजना के तहत प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जा रहा है तथा यहां के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके। इससे योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

48. जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु नए उपकरण लगाए गए हैं, वही राजधानी में विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए एम.आर.आई., एन्डो सर्जरी, ट्रामा यूनिट, पैथालाजी आटो एनालाइजर, हाईटेक रक्त कोष, टेली–मेडीसिन केन्द्र जैसी अनेक सुविधाएं मेडिकल कॉलेज में शुरु की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बहुआयामी स्वरुप देने के लिए, जिला चिकित्सालयों एवं चुनिंदा स्वास्थ्य केन्द्रों में पंचकर्म तथा क्षारसूत्र आयुर्वेद उपचार सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी।

49. आदिवासी अंचल में विशिष्ट रोगों और उनके निदान के शोध तथा अनुसंधान को प्रेरित करने के साथ ही, चिकित्सा शिक्षा में वृद्धि के लिए बस्तर तथा रायगढ़ में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का निर्णय लेकर निजी क्षेत्र के साथ गुणवत्तापूर्ण प्रबंधकीय भागीदारी की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सुचारु रुप से संचालन के कारण शिशु मृत्यु दर, सामान्य मृत्यु दर, जन्म दर, कुष्ठ रोग प्रभाव दर, याज प्रभाव दर, क्षय प्रभाव दर, मलेरिया, आंत्रशोध, पीलिया, अतिसार, खसरा आदि के प्रचलन दर में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है।

50. मेरी सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति का लाभ राज्य के निवासियों को दिलाने के लिए भी व्यापक प्रबंध किए हैं। "राज्यस्तरीय आयुर्वेद शोध एवं अनुसंधान केन्द्र" स्थापित करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। रायपुर के आयुर्वेद महाविद्यालय को प्रदेश के मॉडल कॉलेज का स्वरुप प्रदान किया जा रहा है। आयुर्वेदिक औषधियों की जांच हेतु प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण किया गया है। विशेष अभियान के अंतर्गत 2 हजार से कम जनसंख्या वाले 100 ग्रामों में सामान्य रोगों के उपचार हेतु विशिष्ट 15 आयुर्वेदिक औषधियां निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को संविदा आधार पर नियुक्ति प्रदान कर, आदिवासी क्षेत्रों की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

51. प्रदेश में अभी 7 वृहद, 8 मध्यम तथा 463 लधु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। विगत दो वर्षों में 83 योजनाओं से 1.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता अर्जित की गई, वहीं 2004–05 में 80 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा रहा है। राज्य की विभिन्न बड़ी नदियों पर 190 एनीकट चिन्हित किए गए हैं, जिनकी लागत 700 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा छोटे–छोटे, नदी–नालों में लगभग 589 स्टापडेम–एनीकट निर्माण की योजनाएं चिन्हित की गई हैं। इन योजनाओं से हजारों हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई संभव हो सकेगी। साथ ही कृषकों को निस्तार हेतु जल उपलब्ध होगा और भूजल स्तर में वृद्धि हो सकेगी।

52. मेरी सरकार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों को शुद्ध पेयजल सुलभ कराने तक ही सीमित नहीं मानती, बल्कि इसे व्यापक सामाजिक परिवेश में शुद्धता के जनअभियान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रुप में स्वीकार करती है। इस जिम्मेदारी के तहत विगत वर्ष 2 हजार 777 बसाहटों में शुद्ध पेयजल का इंतजाम किया गया। 762 नल–जल योजनाएं तथा 422 स्पॉटसोर्स योजनाएं, पूर्ण कर ग्राम पंचायतों को सौंपी जा चुकी हैं। भूजल संवर्धन की 9.47 करोड़ रुपए की 30 योजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। शुद्ध पेयजल की जांच के लिए 10 प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। "स्वजलधारा–एक" योजना के तहत 14 जिलों में 6 करोड़ रुपए से अधिक की 312 योजनाएं तथा "स्वजलधारा–दो" के तहत 40 करोड़ रुपए की योजनाएं भी मंजूर कराई गई हैं। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत 6 जिलों में 9 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक की योजनाएं स्वीकृत कराई गई तथा 10 अन्य जिलों में 158 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं।

53. शहरी जल प्रदाय कार्यक्रमों के अंतर्गत 6 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 20 हजार से कम आबादी वाले नगरों में भी 13 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इस तरह राज्य में शुद्ध पेयजल के साथ सम्पूर्ण परिवेश की स्वच्छता पर व्यापक जनभागीदारी से बहुत बड़ा अभियान संचालित किया जा रहा है। जिससे राज्य में अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली का वातावरण बन रहा है।

54. विद्युत तथा ऊर्जा के साधनों की उपलब्धता और खपत की कसौटी पर ही यह तय होता है कि राज्य विकासोन्मुखी है। मेरी सरकार ने इस कसौटी पर खरा उतरने के लिए चहुंमुखी प्रयास किए हैं। एक ओर जहां विद्युत उत्पादन बढ़ाने पर यथोचित ध्यान दिया जा रहा है, वहीं वैकल्पिक स्रोत्रों के नए रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। हर वर्ग के उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदाय के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर 15 अति उच्चदाब केन्द्र, 173 उच्चदाब केन्द्र और संबंधित लाइनों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2007 तक "प्रत्येक गांव में बिजली" और वर्ष 2012 तक "घर–घर में बिजली" के लक्ष्य को पूरा करने के लिए श्रृंखलाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं।

55. ताप विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सकारात्मक वातावरण बनाया गया, उसके परिणामस्वरूप कोरबा पूर्व में ताप बिजलीघर का निर्माण शुरू कर दिया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में कोरबा पूर्व तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में कोरबा पश्चिम ताप विद्युत परियोजनाओं के कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएंगे, जिसके लगभग 1000 मेगावाट की क्षमता प्राप्त की जाएगी। मेसर्स लेन्कों अमरकंटक द्वारा 250 मेगावाट की क्षमता के बिजलीघर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। यह सिलसिला लगातार चलता रहे, इसके लिए भैयाथान में राज्य विद्युत मंडल द्वारा 1320 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना, इंद्रावती नदी पर 60 मेगावाट की मटनार जल विद्युत परियोजना तथा बोधघाट जलविद्युत परियोजना के तहत 500 मेगावाट क्षमता के बिजलीघरों के निर्माण की योजनाएं भी बनाई गई हैं। इस तरह व्यापक दूरदर्शिता के साथ ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत किया जा रहा है। सौर ऊर्जा तथा कृषि अपशिष्ट यथा धान की भूसी तथा पशु अपशिष्टों से भी विद्युत तथा बायोगैस उत्पादन की ओर ठोस कदम बढ़ाए गए हैं। धान की भूसी से ही 200 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन हेतु निजी संस्थाओं को अनापत्ति दी गई है।

56. केन्द्रीय क्षेत्र से छत्तीसगढ़ को आबंटित 498 मेगावाट के अंश को घटाकर 210 मेगावाट कर दिए जाने से, राज्य में पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराने की चुनौती बढ़ गई है। विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच कतिपय अंतर को सुनियोजित प्रबंधन से समायोजित करना होगा और यह कार्य व्यापक जनसहयोग से ही किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि आप सब इस विषय की गंभीरता को भली–भांति समझकर अपने–अपने स्तर पर सकारात्मक सहयोग करेंगे। साथ ही मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी सरकार ऐसा प्रबंध करने में सक्षम है, जिससे ऐसी समस्याओं का निदान भी हो जाए।

57. छत्तीसगढ़ में बहुतायत में पाई जाने वाली वनस्पति रतनजोत के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देकर बायोडीजल बनाने की दिशा में भी मेरी सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना हाथ में ली है। 'छत्तीसगढ़ बायो–फ्यूल विकास प्राधिकरण' का गठन किया गया है। शोध, अनुसंधान और रतनजोत के उत्पादन और डीजल निर्माण की प्रक्रिया से गुजरते हुए बायो डीजल पंपों की स्थापना तक का लंबा सफर तय करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इन प्रयासों से कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ को डीजल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

58. राज्य में उपलब्ध संसाधनों, स्थानीय आबादी के विकास की जरूरतों और पूंजी निवेश की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने नई औद्योगिक नीति लागू की है। यह देश में सबसे आकर्षक नीति मानी जा रही है, जो एक ओर निवेशकों को यथोचित सुविधाएं प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सुनिश्चित करती है। नई औद्योगिक नीति में विशेष थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत चिन्हित उद्योगों को अनेक रियायतें और अनुदान दिए जाएंगे, वहीं सरकार द्वारा घोषित कराध ाान संबंधी वित्तीय सुविधाएं तथा रियायतें तभी दी जाएंगी, जब ये उद्योग अकुशल श्रमिकों की श्रेणी में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामले में 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय वर्ग में न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को देंगे।

59. मेरी सरकार ने 'राज्य निवेश प्रोत्साहन अधिनियम' में संशोधन कर इसे और अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी बनाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित 'राज्य निवेश प्रोत्साहन मंडल' तथा 'एकल बिन्दु निवेश संपर्क' के जरिए निश्चित समयावधि में उद्यमियों को समस्त अनुमतियों एवं अनुज्ञाएं जारी करने का काम, अब अधिक सक्षमता से कर पा रहा है। राज्य में पूर्व से स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों हेतु भूमि शेष न रह जाने के कारण, नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना उन्नयन हेतु भी मेरी सरकार ने पर्याप्त प्रावधान किए हैं।

60. इस वर्ष 16 मध्यम और वृहद उद्योग तथा 745 लघु उद्योग उत्पादन प्रारम्भ कर चुके हैं, जिनमें 135 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश हो चुका है। 35 मध्यम तथा वृहद उद्योग निर्माणाधीन हैं तथा अन्य अनेक परियोजनाओं का प्रारंभिक स्तर का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। राज्य सरकार निजी पूंजी निवेश से औद्योगिक क्षेत्र तथा क्लस्टर एप्रोच के आधार पर हर्बल पार्क, फूड पार्क, एल्यूमिनियम पार्क, एपेरेल पार्क, आई.टी. पार्क आदि विकसित करना चाहती है। इस दिशा में सार्थक पहल हो चुकी है तथा रायगढ़ जिले में निजी पूंजी निवेश से लगभग 200 हेक्टेयर भूमिपर एक औद्योगिक क्षेत्र में अनेक मध्यम एवं लघु उद्योग उत्पादन प्रारम्भ कर चुके हैं।

61. छत्तीसगढ़ के गांवों में मौजूद परम्परागत ग्रामोद्योग तथा हस्तशिल्प के कौशल को गांव वालों की आर्थिक समृद्धि का जरिया बनाने हेतु अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। नैसर्गिक कोसा प्रगुणन एवं संग्रहण

योजना के तहत 4 जिलों में 8 बीज प्रगुणन केन्द्र लगाए गए। पालित डाबा टसर ककुन उत्पादन योजना के तहत कीर्तिमान उत्पादन करीब 3 करोड़ नग किया गया। वन आधारित ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देकर लगभग 52 हजार लोगों को लाभान्वित किया गया।

62. राज्य के बुनकरों को अनेक नवीन योजनाओं, जैसे रिवाल्विंग फंड तथा कार्यशाला जीर्णोद्धार योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। उनके लिए दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन योजना सहित अनेक योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। एक हजार बुनकरों को केन्द्रीय बुनकर सेवा केन्द्र के सहयोग से उन्नत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य में 'भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान' की स्थापना जांजगीर–चांपा जिले में की जा रही है। इससे प्रतिवर्ष 30 छात्र हेण्डलूम टेक्नालॉजी का त्रिवर्षीय डिप्लोमा प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही प्रदेश के बुनकरों को नई–नई डिजाईन तकनीक का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित केन्द्रों में पांच हजार व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 'उत्पादन अनुदान' एवं 'कत्तिन अनुदान योजना' लागू की जा रही है।

63. हस्त शिल्पियों की समृद्धि के लिए 'छत्तीसगढ़ हस्त शिल्प विकास बोर्ड' का गठन किया गया है। इसके तहत सरगुजा में 'सामान्य सुविधा केन्द्र, स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का हस्तशिल्प विदेशी बाजारों में पहुंचाने के लिए 14 देशों सहित भारत के निर्यातकों के माध्यम से नेटवर्क बनाया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में फ्रांस निर्यात हेतु प्राप्त हुए हस्तशिल्प क्रय के आदेश की पूर्ति भी कर दी गई है।

64. खनिजों की चमक प्रदेश में नए उद्योगों को आकर्षित कर रही है। मेरी सरकार ने खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए, ऐसे आवेदकों को खनि रियायतें देने में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है, जो उत्पादित खनिज का उपयोग राज्य में वेल्यू–एडीशन के लिए करें। आधुनिक तकनीक का उपयोग कर हीरा, सोना जैसे बहुमूल्यों खनिजों तथा निकल, तांबा, जस्ता जैसी धातुओं के खनिजों की खोज के लिए विगत एक वर्ष में 8 हजार 475 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर 5 रिकोनेसेन्स परमिट देने का अनुमोदन किया गया है। एक वर्ष के सर्वेक्षण उपरान्त चूनापत्थर के एक हजार 250 लाख टन, कोयला के 360 लाख टन, बॉक्साइट के 20 लाख टन तथा लेपीडोलाइट के 50 हजार टन अतिरिक्त भण्डार चिन्हित किए गए। मेरी सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि जिन खनिजों के खनन में कम निवेश की आवश्यकता होती है, उनका दोहन राज्य खनिज निगम के माध्यम से संयुक्त उद्यम कंपनियां गठित करके किया जाए, ताकि रायल्टी के साथ–साथ खनिजों से होने वाली आय का एक हिस्सा भी राज्य सरकार को मिले।

65. मेरी सरकार ने अपने संकल्पों को पूरा करने की दिशा में अनेक कदम उठाते हुए शहरों के विकास हेतु अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इनसे सुनियोजित बसाहट के साथ नागरिक–सुविधाएं और पर्यावरण की सुरक्षा बढ़ने लगी है। इन योजनाओं में कमजोर तबकों को रोजगार के नए अवसर भी जुटाए जा रहे

हैं।'दीनदयाल स्वावलम्बन योजना' के तहत राज्य में पौने चार करोड़ रूपए की लागत से करीब ढाई हजार गुमटियां बनाई जा रही हैं, जो छोटे कारोबारियों को सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराएंगी। 'मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना' के तहत 11 करोड़ रूपए की लागत से 8 हजार से अधिक दुकानें बनाई जा रही हैं, जिनमें 750 तो सिर्फ महिलाओं के लिए पृथक बाजार के रूप में रहेंगी।

66. आवास निर्माण के क्षेत्र में एक नई क्रांति का जन्म हुआ है। 'दीनदयाल आवास योजना' के तहत 200 करोड़ रूपए की लागत से 10 हजार मकान बनाकर कमजोर तबकों को दिए जा रहे हैं। अटल आवास योजना के तहत 3 हजार मकान बनाए जा रहे हैं। मध्यम तथा अन्य आय वर्ग के लोगों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने हेतु 'गृह निर्माण मण्डल' सुनियोजित रणनीति के तहत अच्छी गुणवत्ता और कम लागत के मकान बनाकर सार्थक भूमिका का निर्वाह करने लगा है। शहरों में स्वच्छ पर्यावरण और व्यवस्थित बसाहट के लिए गोकुल नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, सरोवर–धरोहर जैसी योजनाएं गति पकड़ चुकी हैं।

67. 'मुख्यमंत्री श्रमवीर कल्याण योजना' के तहत प्रदेश के 26 हजार से अधिक रिक्शाचालकों को वर्दी, परिचय पत्र, चिकित्सा, शेड आदि सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस योजना में किराए पर लेकर रिक्शा चलाने वाले लोगों को रिक्शे का मालिकाना हक भी दिलाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए उन्हें ऋण और आर्थिक मदद दी जा रही है। इतना ही नहीं, रोजगार के अवसरों की तलाश और तद्नुसार युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी युवजन विकास योजना' भी शुरू की गई है, जिसके तहत पहले चरण में चार हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कार्य एक अनुभवी तथा प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से कराया जा रहा है। प्रत्येक युवा के प्रशिक्षण पर 3 हजार रूपए खर्च होंगे।

68. मेरी सरकार ने विकास कार्य को जितना जरूरी समझा, उतना ही जरूरी प्रदेश की जनता को त्वरित न्याय दिलाने को भी माना। इस हेतु राज्य के सभी 16 राजस्व जिलों को सिविल जिला बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें कबीरधाम और कोरबा को सिविल जिला बना दिया गया है। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्राथमिकता से कार्यवाही की जा रही है। 6 अतिरिक्त परिवार न्यायालय का गठन शीघ्र किया जा रहा है। विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा जेल से ही उनकी सुनवाई हेतु वीडियो कॉन्फरेंन्सिंग व्यवस्था लागू करने की कार्यवाही की जा रही है।

69. सुनामी लहरों की आपदा से पीड़ित तटवर्ती राज्यों को तत्काल राहत भेजने के लिए मेरी सरकार द्वारा 7 करोड़ रूपए के पैकेज की घोषणा की गई। मेरी कामना है कि प्रभावित राज्यों में दो गांवों को गोद लेकर वहां पुनर्वास के समस्त कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न हों। सुनामी राहत के लिए आम जनता द्वारा की गई मदद के लिए मैं इस सदन के माध्यम से सभी को साधुवाद देता हूं।

70. प्रदेश में सूखे की स्थिति को देखते हुए 15 जिलों की 85 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इन तहसीलों में राहत कार्यों के संचालन हेतु केन्द्र सरकार से लगभग 605 करोड़ रूपए की राशि तथा 7 लाख मीट्रिक टन चावल की मांग की गई है। इस बीच राज्य सरकार द्वारा लाखों लोगों को प्रतिदिन रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे अब राज्य में मजबूरीवश पलायन की स्थिति नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों की मदद का जज्बा छत्तीसगढ़वासियों की विशेषता है। आपदा पीड़ितों को संबल और हर संभव मदद दिलाने के लिए आप सभी को केन्द्र के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए साधुवाद देता हूं। राज्य में समय–समय पर प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को अधिक सुविधाएं देने के लिए, मेरी सरकार ने विभिन्न प्रकरणों में दी जाने वाली सहायता राशि में भी बढ़ोत्तरी की है।

71. मेरी सरकार, राज्य के दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं के विस्तार हेतु कृतसंकल्प है। अंतर्राज्यीय परिवहन को सुचारू बनाने हेतु पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेश के साथ प्रारंभिक पारस्परिक परिवहन समझौता सम्पन्न कर लिया गया है। अन्य पड़ोसी राज्य से भी पारस्परिक समझौते हेतु पहल जारी है। राज्य के भीतर यात्री बसों के सुगम संचालन हेतु मार्गों का निर्धारण किया गया है।

72. वाहन स्वामियों की सुविधाएं बढ़ाने तथा डुप्लीकेशन एवं फर्जी प्रकरणों पर नियंत्रण हेतु लायसेंस एवं वाहन की पंजीयन की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण कर 'स्मार्ट कार्ड' जारी करने की योजना है। इस प्रकार प्रदेश की दो प्रमुख परिवहन जांच चौकियों क्रमशः पाटेकोहरा एवं भगतदेवरी में पांच विभागों की एकीकृत कम्प्युटरीकृत जांच चौकी शीघ्र स्थापित करने की योजना है। आम जनता की सुविधा हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 8 जिलों में नए परिवहन कार्यालय खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

73. मेरी सरकार, कानून और व्यवस्था का राज कायम करने की दिशा में व्यापक जनभागीदारी, नवीन प्रौद्योगिकी, कुशल प्रबंधन और विश्वास बढ़ाने की रणनीति पर चल रही है। इससे राज्य में भय और दमन मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था कायम की जा सकी है। अपराधी तत्वों के हौसले पस्त हुए हैं और राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने वाली शक्तियां एकजुट होकर योगदान कर रही हैं। यही शांति, अमन तथा चैन का वातावरण अन्य प्रदेश के लोगों का ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित कर रहा है। राज्य में पुलिस की कार्यक्षमता और मनोबल बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत समुचित संसाधन उपलबध कराए गए हैं। नक्सली समस्या के समाधान हेतु संसाधनों की कमी को दूर करने के लिये, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की सात बटालियन केन्द्र से प्राप्त की गई हैं। एक अतिरिक्त 'भारत रक्षित वाहिनी' की मंजूरी भी मिली है। सूरजपुर पुलिस जिले का गठन किया गया है। पुलिस बल को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए कांकेर जिले में 'जंगल वारफेयर स्कूल' की स्थापना की जा रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में समग्र विकास की दिशा में जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा

रहा है। नक्सल पीड़ित एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए मेरी सरकार द्वारा पुनर्वास योजना भी लाई गई है। मेरी सरकार ने जेलों को सुधारगृह बनाने की दिशा में सार्थक पहल करते हुए, जेलों में संचालित उद्योगों में कार्य करने वाले बंदियों की पारिश्रमिक दरों में वृद्धि की गई है।

74. मेरी सरकार जनकल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर चलने और उसे मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। निचले स्तर तक लोकतंत्र की स्थापना और सबसे कमजोर तबके को तरक्की का अवसर मिलना ही, लोकतांत्रिक सरकार की सफलता तथा उसकी लोकप्रियता का असली पैमाना हो सकता है। विकास के चौतरफा प्रयासों से ही राज्य में शांति और खुशहाली आती है। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार के दृष्टिकोण और प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है। यह राज्य के विकास का महत्वपूर्ण संकेत है और इसके लिए आप सब जनता के नुमाइंदे बधाई के पात्र हैं। अपनी परम्पराओं और सद्भावपूर्ण विकास के रास्ते पर चलकर आप छत्तीसगढ़ को देश का समृद्धतम राज्य बनाएंगे, यह आशा अब विश्वास में बदल रही है। मेरी कामना है कि इसकी गति बनाए रखने के लिए आपके सहयोग मेरी सरकार को मिलेगा।

जय हिन्द । जय छत्तीसगढ़ ।